शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक-9 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 19-26 फरवरी 2024 मूल्य पांच रूपये

जब सचेतक नियुक्त ही नहीं तो सचेतकीय परिपत्र कौन जारी करेगा? क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ा

- जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिये सचेतकीय परिपत्र जारी नही हो सकता तो सदस्य के चुनाव में कैसे हो सकता है?
- क्या राज्यसभा का चुनाव सदन के भीतर की कारवाई मानी जा सकती है?
- क्या पोलिंग ऐजैन्ट सचेतक की भूमिका निभा सकता है
- क्या मन्त्री सचेतक भी हो सकता है?

शिमला/शैल। क्या 27 तारीख को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने जा रही है। यह सवाल इसलिये चर्चा में आया है क्योंकि 25 विधायकों वाली भाजपा ने राज्यसभा के लिये उम्मीदवार दिया है। भाजपा का उम्मीदवार पूर्व कांग्रेसी है। पार्टी छोड़ते समय वह कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष था। पूर्व मंत्री है और स्व. वीरभद्र सिंह के विश्वास पात्रों में रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ ही उसके संबध जग जाहिर है। हर्ष महाजन की यह कांग्रेसी पृष्ठभूमि इस चुनाव में इसलिये महत्वपूर्ण हो जाती है कि कांग्रेस के इसी के उम्मीदवार देश के वरिष्ठ वकील सिंधवी प्रदेश से बाहर के हैं। इसी के साथ वह सुक्खू सरकार के वाटरसैस लगाने को चुनौती देने वाली कंपनियों के वकील हैं और यही कांग्रेस के लिये एक बड़ी हास्यस्पद स्थिति पैदा कर देती है। वाटरसैस लगाना सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला है और इस फैसले का शीर्ष अदालत में विरोध करने वाले को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना सरकार के हर फैसले पर सैद्धान्तिक प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता है।

इस सैद्धान्तिक सुविधा के साथ यदि सरकार के गठन से लेकर अब तक की वस्तुस्थिति पर नजर डाली जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की कथनी और करनी में दिन-रात का अन्तर रहा है। मंत्रिमण्डल के पहले विस्तार से पहले ही मुख्यमंत्री को छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां क्यों करनी पड़ी? यह मामला उच्च न्यायालय में भी पहुंच चुका है लेकिन जनता में इसका जवाब नहीं आया है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को श्रीलंका जैसी बताने के साथ ही मुख्यमंत्री को एक दर्जन से अधिक गैर विधायकों को सलाहकारों आदि के रूप में ताजपोशियां क्यों देनी पड़ी? इन ताजपोशीयों के बाद सरकार को मित्रों की सरकार का तमगा क्यों मिला? मंत्रिमण्डल में क्षेत्रीय असन्तुलन दूसरे विस्तार के बाद भी बना हुआ है। पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का सरकार में उचित समायोजन न हो पाना लगातार मुद्दा बना हुआ है। इस आश्य की शिकायत हाईकमान तक पहुंची हुई है। बेरोजगारों के मुद्दे पर कांग्रेस के ही वरिष्ठ विधायक सरकार को खुला पत्र लिखने पर बाध्य हो गये हैं। कर्मचारियों के कई वर्ग धरने प्रदर्शनों तक पहुंच चुके हैं। गारंटीयां चुनावों में गले की फांस बनने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर हाईकमान तक इस लगातार बढ़ते रोष का संज्ञान नहीं ले रहा है। पार्टी में त्यागपत्रों की रणनीति अभिषेक राणा से शुरू होकर मण्डी के समस्त पदाधिकारी तक पहुंच गयी है और कहां रुकेगी यह आने वाला समय ही बतायेगा।

इस वस्तु स्थिति को लेकर पार्टी का हर बड़ा नेता चिन्तित है लेकिन मुख्यमंत्री पर किसी चीज का कोई असर नहीं है। वह अपने अपरिभाषित व्यवस्था परिवर्तन के जुमले को पकड़कर बैठे हुए हैं। ऐसे में जो लोग सही में प्रदेश और पार्टी की चिन्ता कर रहे हैं उनके सामने इस राज्यसभा चुनाव में अपने रोष को व्यवहारिक रूप से प्रकट करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। सरकार का बजट केवल कर्ज बढ़ाने वाला है इसमें बेरोजगारी और महंगाई से निपटने की कोई ठोस योजना नहीं है। ऐसे में हाईकमान को अपने रोष से व्यवहारिक रूप से अवगत करवाने के लिये इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग ही एकमात्र विकल्प माना जा रहा है। क्रॉस वोटिंग से ऐसा करने वालों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि पार्टी अभी तक सचेतक नियुक्त नहीं कर पायी है जब सचेतक है ही नहीं तो व्हिप कैसे जारी होगा? फिर जब व्हिप राष्ट्रपति चुनाव पर लागू नही होता है तो राज्यसभा सदस्य के चुनाव पर कैसे लागू होगा? व्हिप सदन की कार्यवाही पर लागू होता है। किसी विधेयक आदि के पारण में यह व्यवस्था लागू होती। क्योंकि सचेतक का प्रावधान संविधान में नहीं है और न ही सदन के नियमों में। जब 1992 में सचेतक का प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था तब इसमें एक लाईन, दो लाईन और तीन लाईन के सचेतकीय परिपत्र की व्यवस्था की गयी थी। एक लाईन और दो लाईन के परिपत्र की

शेष पृष्ठ 8 पर.....

क्या सुक्खू सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है?

अनुबन्ध का विकल्प तलाशने से उठी चर्चा

शिमला/शैल। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान जो दस गारंटीयां जनता को दी थी उनमें से एक युवाओं को रोजगार देने की थी। सरकार ने इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए तीन मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर सरकार में खाली पदों की जानकारी हासिल करने का प्रयास किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में 70,000 पद खाली होने की जानकारी आयी थी। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 185698 पद नियमित 5726 अंशकालिक और 4593 दैनिक वेतन भोगी है। तदर्थ और अनुबन्ध आदि की जानकारी सर्वेक्षण में नहीं दी गयी है ऐसा क्यों है इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। सरकार में 70,000 पद खाली होने से युवाओं में नौकरी मिलने की उम्मीद बंधी थी। लेकिन विधानसभा के इस बजट सत्र में जिस भी विधायक ने यह जानकारी मांगी है कि 15-01-24 तक सरकार कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा पायी है तो इसमें ''सूचना एकत्रित की जा रही है'' का ही जवाब आया है। सरकार इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार ने एक समय अनुबन्ध के आधार पर सरकारी नौकरी देने का नियम बनाया था। एक तय समय अवधि के बाद ऐसे नियुक्त हुये कर्मचारी नियमित हो जाते थे। लेकिन इन्हें पूरे सेवा लाभ नहीं मिल पाते थे और यह सरकार की बचत होती थी परन्तु पिछले दिनों तीन कान्ट्रेक्ट के अलग-अलग मामलों में यह व्यवस्था दी है कि कान्ट्रेक्ट काल सारे सेवा लाभों पदोन्नति और पैन्शन आदि में गणना में आयेगा तो उससे सरकार के लिये कठिनाई बढ़ी है। बल्कि कान्ट्रेक्ट की जगह नियमित नौकरी देने को ही बेहतर माना जा रहा है। इस समय

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राजभवन में अरूणाचल और मिज़ोरम का स्थापना दिवस आयोजित

शिमला/शैल। अरूणाचल प्रदेश और मिज़ोरम राज्यों के स्थापना दिवस पर राजभवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इन राज्यों के हिमाचल प्रदेश में रह रहे नागरिकों को हिमाचली

टोपी, शॉल और गमला भेंट कर सम्मानित किया और उनके साथ संबंधित राज्यों की संस्कृति, धरोहर, रीति-रिवाज़ और उच्च परम्पराओं पर विस्तृत चर्चा की। लेडी गवर्नर एवं राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा जानकी शुक्ला भी उपस्थित थीं।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राजभवन नियमित तौर पर देश के विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है और उन राज्यों से संबंधित व्यक्तियों को राजभवन में आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित करता है और सामुहिक तौर पर उनकी खुशी में शामिल होता है। ये सभी कार्यक्रम ''एक भारत, श्रेष्ठ भारत'' की परिकल्पना को साकार करने के दृष्टिगत आयोजित किए जा रहे हैं ताकि भारत की एकता और अखंडता और मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हर राज्य की अपनी विविध संस्कृति है और यही विविधता भारत की ताकत भी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों, परंपराओं और प्रथाओं के संपर्क से राज्यों के बीच समझ और जुड़ाव और बढ़ेगा।

शुक्ल ने हिमाचल में रह रहे अरूणाचल प्रदेश और मिज़ोरम राज्यों के नागरिकों को राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केन्द्र शासित राज्य बनाया गया था, 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वाँ राज्य बना। आज अरुणाचल प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीमा से सटे गांवों को वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज का दर्जा देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सीमा से सटे हर गांव में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे, वहीं से समृद्धि की शुरुआत होगी। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के तहत सरहदी गांवों से पलायन को रोकने और वहां पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि 20 फ़रवरी 1987 को मिज़ोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मिज़ोरम शब्द का स्थानीय मिज़ो भाषा में अर्थ है, पर्वतनिवासीयों की भूमि। मिज़ोरम में शिक्षा की दर तेजी से बढ़ी हैं। मिज़ो समाज में वर्ग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता। इनमें से 90 प्रतिशत लोग कृषक हैं और गाँव एक बड़े परिवार की तरह होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों ने यहां की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है और अपनी विकासात्मक सोच से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। ये राज्य पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक तो है ही लेकिन यहां की संस्कृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास में यहां रहे रहे इन राज्यों के नागरिक भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

इस अवसर पर, अरूणाचल प्रदेश और मिज़ोरम राज्यों के धरोहर नगरो, स्मारकों और संस्कृति को लेकर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। दोनों राज्यों के राज्यपालों के संदेश भी प्रसारित किए गए। इस अवसर पर इन राज्यों के नागरिकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राज्यपाल को विश्वभर में श्री राम पर जारी स्मारक डाक टिकट की पुस्तिका भेंट की

शिमला/शैल। प्रदेश के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अम्बेश उपमन्यु ने डाक विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में भेंट की। उन्होंने इस अवसर

पर राज्यपाल को विभिन्न देशों में श्री राम पर जारी डाक टिकटों से संबंधित एक पुस्तिका, अयोध्या की मिट्टी और सरयु नदी का जल भेंट किया।

उन्होंने राज्यपाल को अवगत करवाया कि 18 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या के राम मन्दिर पर छः स्मारक डाक टिकट का सेट जारी किया गया है। इन डाक टिकटों में श्री राम जन्म भूमि की मिट्टी एवं जल को अन्तर्निहित करते हुए इसमें चन्दन की खुशबू का समावेश किया गया है। इन डाक टिकटों को आलोकित करने के लिए इनके लघु चित्रों पर सोने की सूक्ष्म परत भी चढ़ाई गई है।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश डाक वृत्त में 19 फरवरी, 2024 तक राम जन्म भूमि से संबंधित 3800 स्मारिकाएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सदेश के साथ इन स्मारिकाओं को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत प्रधानों तक पहुंचाया जाएगा।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा तथा डाक विभाग के विकास नेगी भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने दिव्यांगजनों के समावेशी विकास में चेतना संस्था के प्रयासों को सराहा

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बिलासपुर जिला के विजयपुर में चेतना संस्था के रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। महिला सशक्तिकरण की दिशा

में चेतना संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति समर्पित प्रयासों तथा कमजोर वर्गो के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में यह संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राज्यपाल ने कहा कि चेतना संस्था की हिमाचल इकाई दिव्यांगजनों के समावेशी एवं सतत विकास में सराहनीय कार्य कर रही है। संस्था उनका सशक्तिकरण करते हुए दिव्यांगजनों को खेलों से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ ही उन्हें समान अवसर, अधिकार और सम्मानित जीवन सुनिश्चित किया है जो सभी के लिए प्रेरक है। उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि संस्था दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्पित भावना से कार्य कर रही है।

हिमाचल में अपने एक साल के कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए राज्यपाल ने प्रदेश में नशे जैसी बुराई के खात्मे के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने इसके लिए एक सघन जागरूकता अभियान आरम्भ करने का आग्रह करते हुए कहा कि पंचायत स्तर तक नशा मुक्ति के दृष्टिगत ऐसे बच्चों के माता-पिता को भी आगे आकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहल करते हुए विश्वविद्यालयों को दाखिले के समय छात्रों से नशा न करने संबंधी शपथ पत्र लेने के लिए कहा गया है। साथ ही नशाखोरी में शामिल छात्रों के विरूद्ध कड़ी कारवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नशे की बुराई के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग इत्यादि लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

राज्यपाल ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और इस युवा ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने से ही भारत वर्ष-2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा। उन्होंने कहा कि आज देश अपनी क्षमताओं में विश्वास जताते हुए उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर राज्यपाल ने जन शिक्षण संस्थान के आत्मनिर्भर एवं सशक्त महिला पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवा स्टार्ट-अप, किसान और कृष्णा ऊन उद्योग-बिवाई पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही चेतना संस्था के अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया।

इससे पूर्व राज्यपाल ने चेतना संस्था द्वारा लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान के डिजिटल लॉन्च में भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

चेतना संस्था की संस्थापक एवं विशेष ओलम्पिक की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा ने राज्यपाल का स्वागत किया और संस्था की गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि संस्था नशे से बचाव के दृष्टिगत युवाओं के लिए एक विशेष अभियान भी चला रही है।

चेतना संस्था के अध्यक्ष पुरूषोतम शर्मा, विशेष अतिथि रूमा बनर्जी ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। संस्था के उपाध्यक्ष मनोज शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

विधायक जीत राम कटवाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

डाइट मनी में पांच गुणा बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

शिमला/शैल। पुलिस विभाग के एक प्रतिनिधिमण्डल ने पुलिस

महानिदेशक संजय कुंडु के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और डाइट मनी में पांच गुणा बढ़ोतरी के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने इस बार के बजट में पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को बढ़ाकर एक हजार रुपये करने की घोषणा की है। प्रतिनिधिमण्डल ने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि पूर्व में किसी भी सरकार द्वारा इस तरह का प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

इस अवसर पर विधायक संजय रत्न भी उपस्थित थे।

निर्देशक विवेक अग्निहोत्री बने मानव मन्दिर के ब्रांड एम्बेसेडर

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन जिला के कोठू स्थित इंटीग्रेटिड मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी री-हेबिलिटेशन सेन्टर मानव मन्दिर के ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में विख्यात फिल्म निर्माता एवं निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का नाम औपचारिक तौर पर घोषित किया। उन्होंने राजभवन से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके लिए विवेक अग्निहोत्री को बधाई भी दी। इस अवसर पर मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित रोगी भी राजभवन में उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि मांसपेशियों से संबंधित इस रोग का उपचार संभव है और इस केंद्र में फिजियोथैरेपी, होइड्रोथैरेपी, योगा तथा प्राणायाम सहित आधुनिक मशीनों के माध्यम से उचित देखभाल की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इस केंद्र की सराहना कर चुके हैं।

राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि इस केंद्र में उपलब्ध सेवाओं के प्रचार-प्रसार में विवेक अग्निहोत्री अपनी भूमिका बखूबी निभाएंगे और इन प्रयासों से अधिक से अधिक लोगों को इस केंद्र के सहयोग के लिए भी प्रेरित करेंगे। उन्होंने लोगों का आहवान किया कि वे इस केंद्र से जुड़कर मानव सेवा में अपना बहुमूल्य सहयोग दें।

इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े विवेक अग्निहोत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें समाज सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है और वे इसमें सक्रिय रूप से सहयोग देते रहेंगे।

मानव मन्दिर में सेवाएं प्रदान कर रही उमा बाल्दी ने राज्यपाल का स्वागत किया जबकि मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी के रोगी विपुल गोयल ने धन्यवाद किया।

मुख्यमंत्री ने 'हिमाचल प्रदेश लैंड कोड' के नवीन संस्करण का अनावरण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'हिमाचल प्रदेश

लैंड कोड' के नवीन संस्करण का अनावरण किया। इसमें राजस्व एवं अन्य विभागों के भूमि से संबंधित मामलों के कानूनों का संकलन किया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लैंड कोड का प्रथम संस्करण 1992 में प्रकाशित किया गया था तथा 1992 के बाद से इसे संशोधित नहीं किया गया था। इससे पूर्व भी भूमि से संबंधित अनेक कानूनों को संशोधित कर कई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस लैंड कोड में राजस्व एवं अन्य विभागों से संबंधित कुल 64 अधिनियम, 59 नियम तथा लगभग 340 अधिसूचनाएं एवं दिशा-निर्देशों को संकलित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपायुक्त, एसडीएम व तहसील कार्यालयों में यह लैंड कोड उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि विभागीय अधिकारियों को विभिन्न अधिनयम, नियम, अधिसूचनाओं व दिशा-निर्देशों की अद्यतन जानकारी सुगमता से मिल सके। उन्होंने कहा कि इस कोड से उन्हें राजस्व से संबधित मामलों के निपटारे को दक्षता से सुलझाने में मदद मिलेगी तथा भूमि से संबंधित शिकायतों का निवारण जल्द होने से लोगों को भी राहत मिलेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने पहले ही बजट में राजस्व विभाग में नए लैंड कोड संकलित करने का आश्वासन दिया था तथा अब इसे प्रकाशित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रत्येक महीने के अन्तिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आयें हैं।

उन्होंने कहा कि अक्तूबर, 2023 से अब तक राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से रिकार्ड 89091 इंतकाल और 6029 तकसीम के लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होटल वाइल्ड फ्लावर हाल के संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की सशक्त तरीके से पैरवी की थी जिसके फलस्वरूप प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया है।

मुख्यमंत्री ने इस अनुकूल निर्णय का श्रेय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से मामला प्रस्तुत करने के राज्य सरकार के प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास किए और प्रसिद्ध वकील मुकुल रोहतगी के माध्यम से कानूनी लड़ाई में सरकार का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

होटल वाइल्ड फ्लावर ह ल की संपत्ति कई वर्षो से ओबराय समूह के पास थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल के भीतर इसे खाली करने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संपत्ति का कब्जा मिलने के बाद इसके संबंध में भविष्य की कारवाई पर विचार-विमर्श करेगी और हिमाचल के हितों के अनुरूप निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के 15 टिप्परों को रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौड़ा मैदान, शिमला से लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन के लिए 15 टिप्पर को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इनमें से बी एण्ड आर मण्डल शिमला-1 के लिए एक टिप्पर, निरमंड के लिए 3, रामपुर, कल्पा, रोहडू, जुब्बल एवं कोटखाई मण्डल के लिए दो-दो और भावानगर के लिए एक टिप्पर शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को आवश्यक मशीनरी जैसे कि टिप्पर, जेसीबी एवं पोकलेन इत्यादि की खरीद के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मशीनों की कमी की समस्या का हल भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विभाग को और अधिक सशक्त बनाने एवं इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हाल ही में 82 टिप्पर एवं 107 जेसीबी खरीदी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 15 वर्ष पुराने वाहनों को सरकारी संस्थानों से हटाया जा रहा है, जिससे कि आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण सहित भारी वर्फबारी एवं अन्य आपातकालीन

स्थितियों में बचाव कार्यो में तेजी लाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट नजर आती है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में तेजी लायी है ताकि इनका लाभ प्रदेश के लोगों को समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की पहल करते हुए लोक निर्माण विभाग के तहत निविदा प्रक्रिया को सरल कर इसकी अवधि 51 दिन से घटा कर 30 दिन की है ताकि परियोजनाओं कार्यो में तेजी लायी जा सके और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता की सड़कों के निर्माण को अधिमान दिया जा रहा है।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सुरेंद्र पाल जगोटा, उपायुक्त अनुपम कश्यप एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी है भाजपा:राठौर

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी है। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव परिणाम को जिस ढंग से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी वह सब भाजपा के इशारे पर किया गया था, जिसे आज उच्चतम न्यायालय ने नगर निगम चंडीगढ़ के परिणाम को रद्द कर लोकतंत्र की रक्षा की है।

राठौर ने कहा है कि भाजपा किस प्रकार चुनाव परिणामों को अपने पक्ष में कर रही है आज उच्चतम के फैसले ने सिद्ध कर दिया है कि भाजपा के इशारे पर मतपत्रों से भारी छेड़छाड़ कर चुनाव परिणाम अपने पक्ष में किया जा रहा है।

राठौर ने देश के किसानों के साथ हो रहें अत्यचार पर भी रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नही करेगी। उन्होंने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिये हरियाणा सरकार व केंद्र की भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की है।

इस बीच कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह प्रदेश को आपदा के समय राहत राशि पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बारे श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है जिससे वास्तविक स्थिति का पता चल सकें। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रदेश को राहत बारे भ्रामक प्रचार कर रही है जो सहन नही किया जा सकता।

प्रदेश में 3 मार्च को 59,65,170 शिशुओं को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक

शिमला/शैल। सचिव, स्वास्थ्य एम. सुधा देवी ने शिमला में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 3 मार्च, 2024 को आयोजित किए जाने वाले टीकाकरण की तैयारी संबंधी बैठक की अध्यक्षता की।

राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण के महत्व पर बल देते हुए एम.सुधा देवी ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वस्थ बच्चों के लक्ष्य की प्राप्ति से स्वस्थ हिमाचल का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म नियोजन और आशा वर्कर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता से इस अभियान को सफल बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 03 मार्च, 2024 को पांच वर्ष तक के सभी शिशुओं को स्वास्थ्य केन्द्रों, बूथों और मोबाइल टीमों द्वारा पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। प्रदेश के 5,870 बूथों तथा 257 मोबाइल टीमों के माध्यम से 59 लाख, 65 हजार 170 शिशुओं को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को पोलियो की खुराक देने पर विशेष बल दिया जाएगा।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित व्यस्कों का एडल्ट बीसीजी टीकाकरण शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रदेश के छह जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों का एडल्ट बीसीजी टीकाकरण करवाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत बिलासपुर, कांगड़ा, किन्नौर, मण्डी, सिरमौर और ऊना जिला के 2,64,426 लोगों का बीसीजी टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। बीसीजी टीकाकरण टीबी की बीमारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बैठक में राष्ट्रीय पोलियो अभियान और एडल्ट बीसीजी टीकाकरण के सम्बन्ध में की जाने वाली पूर्व तैयारियों के बारे में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई।

डॉ. संजय रनौत ने प्लस पोलियो टीकाकरण और डॉ. रविन्द्र ने एडल्ट बीसीजी पर अपनी प्रस्तुति दी।

निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक प्रियंका वर्मा तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने 'अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण' कार्यक्रम का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रथम बैच में प्रदेश भर से चयनित 102 अध्यापकों को पांच दिवसीय भ्रमण पर भेजा जा रहा है, जो 24 फरवरी को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ने चयनित अध्यापकों को विदेश भ्रमण की किट्स भी प्रदान कीं। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को 98 अध्यापकों का दूसरा बैच अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर भेजा जाएगा।

सभी चयनित अध्यापकों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शिक्षा क्षेत्र की नई तकनीकों से अवगत होने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षा के नए तौर-तरीकों को जानकर अध्यापक और छात्रों के बीच बेहतर समन्वय होने से छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के मामले में 18वें स्थान पर खिसक गया है। वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सक्षम बन सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खोले जा रहे राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में एक अनूठी पहल है और आने वाले दस वर्षो में ये स्कूल सबसे बेहतर शैक्षणिक केंद्र बनकर उभरेंगे, जहां शिक्षा के साथ-साथ खेलों के लिए भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होगी, स्कूलों को स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने का अधिकार दिया गया है तथा क्लस्टर बनाकर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दूसरे बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की सोच प्रस्तुत की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम आगामी वर्षो में दृष्टिगोचर होंगे। नई नीतियों व कड़े फैसलों से हिमाचल प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नाजुक आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी हैं ताकि कर्ज पर निर्भरता को कम से कम किया जा सके।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है जब शिक्षकों का पहला बैच अंतरराष्ट्रीय भ्रमण पर रवाना होने जा रहा है। इससे अध्यापकों को शिक्षा की नई पद्धतियां जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा गठन के बाद से ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भर रही है, ताकि सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी है, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार मानता हूँ, जो उनके बल पर शिक्षित हुआ और अब वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता।
..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

कांग्रेस से आयकर वसूलने के मायने

2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा निकट भविष्य में कभी भी हो सकती है। क्योंकि जो कुछ पिछले दिनों में घटा है उससे यही संकेत सामने आते हैं। इन चुनावों के परिणामों का प्रभाव दूरगामी होगा चाहे जीत वर्तमान सता पक्ष की हो या विपक्ष की। वर्तमान परिस्थितियों ने हर संवेदनशील व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसी के प्रभाव स्वरूप पूर्व नौकरशाहों के एक बड़े वर्ग ने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति पर एक खुला पत्र सर्वोच्च सत्ता के नाम लिखा है इस परिदृश्य में जो महत्वपूर्ण घटा है उस पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। यह सरकार चुनावी चन्दे के लिये जो चुनावी बाण्ड योजना लेकर आयी थी और उस पर कई सवाल उठे थे। उस योजना को सर्वोच्च न्यायालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद विजय माल्या जैसे कई नाम सामने हैं। जिन्होंने देश से भागने से पहले भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों का चन्दा दिया है चण्डीगढ़ के मेयर के चुनाव में जिस तरह की धांधली सामने आयी उससे सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। इस चुनाव को रद्द करते हुये आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को विजयी घोषित करते हुये चुनाव अधिकारी के खिलाफ अवमानना का आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। ई वी एम के खिलाफ आन्दोलन कर रहे वकीलों ने ई वी एम को हैक करके बता दिया है। इससे स्पष्ट संदेश गया है कि भाजपा की जीत का बड़ा कारण ई वी एम है। देश में उन्नीस लाख ई वी एम 2019 से गायब हैं और इस पर किसी भी ऐजैन्सी ने कोई कारवाई नहीं की है। ई वी एम प्रकरण शीर्ष अदालत में पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेगा। इसी के साथ देश में पहली बार आयकर विभाग ने किसी राजनीतिक दल से आयकर वसूला है। आयकर विभाग की यह कारवाई कांग्रेस के खिलाफ की गयी है और उसके बैंक खातों से 65 करोड़ से ज्यादा पैसा निकाल लिया गया है। आयकर विभाग ने यह कारवाई भाजपा या किसी और दल के खिलाफ नहीं की है इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा कांग्रेस से ही डरी हुई है।

वित्तीय मुहाने पर अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष की चेतावनी ने और डरा दिया है। आई एम एफ के मुताबिक भारत का कर्ज जी डी पी का 100% होने जा रहा है। आर्थिकी को समझने वाले जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिये यह सबसे बड़ा काला पक्ष है। आने वाले चुनाव में युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी। हर तीसरा वोटर युवा होगा। सरकार की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक तीन युवाओं में से हर दूसरा बेरोजगार है। रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार के विभागों में ही 90 लाख पद खाली हैं और सरकार इन्हें भरने की स्थिति में नहीं है। यही स्थिति सार्वजनिक उपक्रमों की है। कॉर्पोरेट घरानों में भी रोजगार कम होता जा रहा है कुल मिलाकर देश एक गंभीर दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा नहीं बनने देना चाहते। इसलिये वह धार्मिक ध्रुवीकरण करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विपक्षीय एकता को तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसके लिये अगले कुछ दिनों में ई.डी., सी.बी.आई और आयकर जैसी ऐजैन्सीयों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। जिस तरह से आयकर विभाग ने कांग्रेस के खातों से 65 करोड़ से अधिक की रकम आयकर के नाम पर निकाल ली है उससे यह स्पष्ट संकेत उभरता है कि कांग्रेस की राज्य सरकारों को भी अस्थिर करने का पूरा प्रयास किया जायेगा। जहां जो सरकारें अपने ही कारणों से कमजोर हो रही हैं उन पर अस्थिरता का प्रयोग किये जाने की बड़ी संभावना है।

भारतीय समावेशी राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं गुलाम जिलानी, जिन्होंने रामलला मंदिर के पताका बनाया

गौतम चौधरी

भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। आबादी के हिसाब से यह दुनिया का न केवल सबसे बड़ा देश है, अपितु यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। भारत में विभिन्न संस्कृति के लोग निवास करते हैं। आस्था और मान्यता की यदि बात करें तो यहां की विविधता अद्भुत है। बावजूद इसके देश, संगठित और व्यवस्थित अपनी गति से विकास के आधुनिक मापदंडों पर आगे की ओर बढ़ रहा है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो भारत में न कभी सीरिया वाली स्थिति पैदा हुई है और न ही यहां अफगान या पाकिस्तान जैसे तालिबानी तत्व पैदा हुए। जब-जब वक्त आया भारत के लोगों ने संगठित होकर भौतिक या दैवीय चुनौतियों का सामना किया है।

भारत में एकता और भाईचारे के अनेक उदाहरण हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन की जोरदार तैयारियों के बीच, एक ऐसी घटना सामने आयी जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। यह घटना झारखंड के हजारीबाग की है। एकता और भाईचारे की इस घटना ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी है। दरअसल, हजारीबाग के गुलाम जिलानी ने अपने उत्साह को एक झंडे में व्यक्त किया और खुद के हाथों से एक शानदार झंडे का निर्माण कर दिया। यह झंडा कोई साधारण झंडा नहीं है, इसे अयोध्या के नवनिर्मित भगवान श्री रामलला के मंदिर पर लगाया गया है। इस झंडे की लंबाई 40 फुट और चौराई 42 फुट का बताया जा रहा है। गुलाम जिलानी के द्वारा बनाया गया झंडा अयोध्या के भगवान श्री रामलला के उस मंदिर पर सुशोभित हो रहा है, जिसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकार्पण किया है। श्रद्धा, एकता और भक्ति का इससे बड़ा उदाहरण और दुनिया में कहीं मिल सकता है।

बता दें कि श्रद्धा और भक्ति कि प्रतीक इस पताके पर एक तरफ भगवान हनुमान जी की छवि है तो दूसरी ओर भगवान हनुमान के कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण विराजमान हैं। यह जिलानी की कलात्मकता और समर्पण बड़ा प्रमाण है। बता दें कि गुलाम जिलानी महावीरी पताका बनाने के माहिर शिल्पकार हैं। झारखंड में रामनौमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस दौरान महावीरी पताके की बड़ी मांग होती है। झारखंड के कई मुस्लिम शिल्पकार इस काम को करते हैं और हिन्दू-मुस्लिम एकता का मिशाल प्रस्तुत करते हैं। इस मामले में जिलानी ने बताया, 'मुझे गर्व है कि मेरे द्वारा सिला हुआ झंडा ऐतिहासिक राम मंदिर की शोभा बढ़ाएगा, जिसका सपना 100 करोड़ से अधिक लोग देख रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए निश्चित रूप से अयोध्या जाऊंगा।' जिलानी के इस योगदान को दुनिया किस रूप में देखेगी यह तो पता नहीं लेकिन यह भारतीय संस्कृति की व्यापकता को परिभाषित करती है। यह भारत की संस्कृति और परंपरा को समृद्ध बना रहा है। वैसे भी शिल्प और कौशल को धार्मिक सीमा या परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। जिलानी, अपने पिता अब्दुल शकूर से सिलाई की कला सीखी। जिलानी का परिवार पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं। उन्हें यह कला विरासत में मिली है। उनका कौशल और समर्पण एकता और सहयोग के सार का प्रतीक है, जो भारत की समन्वयवादी संस्कृति को रेखांकित करता है। जिलानी एक मिसाल हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड में ऐसे हजारों की संख्या में मुस्लिम शिल्पकार हैं, जो महावीरी पताकों का निर्माण करते हैं। इसमें वे धर्म या आस्था को नहीं ढुंढते हैं। हजारीबाग, गिरिडीह या कोडरमा में ऐसे कई मुस्लिम कारीगर मिल जाएंगे जो साल के आधे से अधिक समय केवल महावीरी पताके का ही निर्माण करते हैं। रांची में जब रामनौमी का महोत्सव प्रारंभ होता है तो यहां के अधिकतर मुस्लिम शिल्पकार महावीरी झंडा बनाने में व्यस्त हो जाते हैं और बाहर का काम लेना बंद कर देते हैं। यह हिन्दू-मुस्लिम एकता और समावेशी राष्ट्रवाद का बड़ा उदाहरण है।

जियानी का काम भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने की समावेशिता को प्रतिबिंबित करता है। जिलानी जैसी कहानियां याद दिलाती हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव भारत की पहचान ही नहीं भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह बताता है कि भारत की समधर्मी संस्कृति केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है, जहां गुलाम जिलानी जैसे व्यक्ति धार्मिक आधार पर एकता को बढ़ावा देते हैं। भारतीय मुसलमान अपनी कलात्मकता को साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़कर एक उदाहरण के रूप में खड़े हैं। उनका समर्पण एक ऐसी कथा को रेखांकित करता है जहां की एकता विभाजनों से परे है। गुलाम जिलानी की कहानी भारत के समावेशी राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करता है। यह अनेकता में एकता को चिन्हित करता है। भविष्य का भारत इसी आधार पर आकार ग्रहण करेगा। यह हमारी ताकत है और भारत इसी समावेशी ताकत के बदौलत आसन्न चुनौतियों का सामना करेगा।

''शैल'' साप्ताहिक के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित विवरण

1. प्रकाशन स्थान	:	शैल कार्यालय ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज, लक्कड़ बाजार शिमला
2. प्रकाशन अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	:	बलदेव शर्मा
4. राष्ट्रीयता	:	भारतीय
5. प्रकाशक का नाम	:	बलदेव शर्मा
6. पता	:	ऋचा पिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज, रिवोली बस स्टैण्ड लक्कड़ बाजार शिमला
7. सम्पादक का नाम	:	बलदेव शर्मा
8. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो समाचार पत्र के स्वामी और भागीदार या कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक सांझेदार/हिस्सेदार हों	:	कोई नहीं

मैं बलदेव शर्मा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

(बलदेव शर्मा)

मोदी सरकार में यदि परियोजनाओं का शिलान्यास होता है तो उद्घाटन भी उसी कार्यकाल में होता है :नड्डा

शिमला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर में कई नई सुविधाओं का शुभारंभ किया और 'विश्राम सदन' का शिलान्यास किया। इस क्रम में उन्होंने 4 करोड़ की लागत से बने 40 हजार लीटर की क्षमता वाले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और 30 करोड़ की लागत से एडवांस्ड रेडिएशन थैरेपी के लिये लगी आधुनिक मशीनरी सहित अन्य नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के प्रयासों के चलते एम्स बिलासपुर को कई नई सुविधाएं प्रदान हुई है। 3 अप्रैल 2017 को नवरात्रों की षष्ठी तिथि को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एम्स बिलासपुर का शिलान्यास किया था। 5 अक्तूबर 2022 को विजयदशमी के दिन प्रधानमंत्री ने इस संस्थान का उद्घाटन कर बिलासपुर की जनता को दशहरे का उपहार दिया था। आज 4 करोड़ की लागत से बना 40 हजार लीटर की क्षमता वाले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसी तरह रेडिएशन एन्कॉलोजी में एडवांस्ड रेडिएशन थैरेपी के लिए 30 करोड़ की लागत से आधुनिक मशीनरी लगाई गई है और सीटी स्कैन सुविधा शुरू की गई है। आज 350 बेड की क्षमता वाले विश्राम सदन का भी शिलान्यास हुआ है। एम्स बिलासपुर को इन सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री का अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए कहा कि इन सुविधाओं से पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के लिए स्वास्थ्य और इलाज सुविधा कई गुना बेहतर और आसान हो जाएगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में तेज प्रगति और विकास किया है। हर वर्ग को एक नई दिशा मिली है और देश आगे बढ़ने में सफल हुआ है। कोरोना महामारी पूरी शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी थी और कोई भी इसका इलाज और बचाव नहीं जानता था। पाश्चात्य देश सहित पूरे विश्व के बड़े-बड़े नेता मानवता या अर्थव्यवस्था के बीच असमंजस में झूलते रहे और किसे प्राथमिकता से बचाना है इसका फैसला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'जान है तो जहान है' का नारा लगाते हुए दृढ़ता से पूरे देश में लॉकडाउन लगाकर मानवता को सुरक्षित किया। इस बीच 2 महीने में उन्होंने देश को तैयार किया और उस समय मात्र 112 दिन में पूरे देश में लगभग 2500 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाये गये जिनसे भारत की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 3000 टन प्रतिदिन तक पहुंच गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में भारत के वैज्ञानिकों ने मात्र 9 महीने दो दो स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर देश को इस महामारी से बचाया। परिणामस्वरूप देशभर में 220 करोड़ वैक्सीन लगाई गई। भारत ने 100 देशों को वैक्सीन निर्यात की और विश्व मैत्री के तहत 30 करोड़ वैक्सीन कई देशों को मुहैया कराई।

नड्डा ने कहा बिलासपुर में एम्स बनना यहां के स्थानीय लोगों का सपना था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कारण ये सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा 10 साल में चंडीगढ़ पीजीआई में दस गुना निवेश हुआ है। 25 तारीख को बठिंडा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा 'जब मैं एक युवा छात्र था, तो में कहता था शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है', लेकिन व्यावसायिक शिक्षा समाज द्वारा दिया गया विशेषाधिकार है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा जब उनके स्वास्थ्य मंत्री होने के समय मनसुख मंडाविया रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे और मनसुख मंडाविया के कारण स्टंट के दाम कम हुए थे। जनऔषधि के माध्यम से दवाइयों के दाम कम करने में किए गए थे। पहले लोग आयुर्वेद को जनता इतना महत्व नहीं देते थे मगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद और योग को महत्व मिला है। भाजपा सरकार 30 वर्ष की आयु वाले सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार थ्योरेटिव, एलिएटिव, रिहैबिलिएटिव जैसी कठिन से कठिन बीमारियों से लड़ने के लिए कार्य कर रही है। कैंसर के इलाज कीमोथेरेपी से होता है और रोगी की जान भी बच जाती है परन्तु आयुष प्रणाली रोगी में प्रतिरक्षा प्रणाली बनाकर ताकत प्रदान करती है। इसलिए हर बीमारी से लड़ने की लिए आयुर्वेद भी जरूरी है साथ ही योग भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समग्र दृष्टिकोण के साथ देश की स्वास्थ्य नीति को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

नड्डा ने कहा कि 2018 से पहले, मुख्यमंत्री राहत कोष से जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रणाली थी, जिसमें मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मामले के लिए पत्र लिखना होता था। इस प्रणाली में कुछ कमियां थीं जिसके कारण कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिल पाता था। लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जो 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज प्रदान करती है। इस योजना के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव आया है। नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना का भी उल्लेख किया, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इस योजना ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए टीबी के खिलाफ लड़ाई में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने टीबी के बारे में जनता के बीच जानकारी फैलाने और जरूरतमंदों को दवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावशाली 80% सफलता दर हासिल हुई। उन्होंने बताया कि दवा प्रतिरोधी टीबी से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें केंद्रों की संख्या 127 से बढ़कर 792 हो गई है, जो भारत को टीबी मुक्त बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 706 हो गई है। विस्तार केवल कॉलेजों की संख्या तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस सीटें 50 हजार से बढ़कर 1 लाख 8 हजार तक पहुंच गई हैं। यह प्रगति भारत में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए समर्पण को रेखांकित करती है।

नड्डा ने मेडिकल छात्रों से संवाद करते हुए उनसे कहा की छात्रों का सहयोग सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके तहत पॉलिसीस, प्रोग्राम्स, इम्प्लिमेन्टेशन के द्वारा मानवता की सेवा की जा सकती हैं। लोगों की सेवा करना मेडिकल छात्रों के साथ साथ सभी का कर्तव्य है। अध्यक्ष ने बताया कि वे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से चर्चा करते है कि फैकल्टी के बीच एक समन्वय होना चाहिए जिसके तहत बिलासपुर की फैकल्टी दिल्ली एम्स जाये और उसी तरह दिल्ली एम्स की फैकल्टी यहां बिलासपुर में आकर नई चीजें सीखें और अपने कार्यक्षेत्र में उसका उपयोग करें। नड्डा ने एम्स की व्याख्या करते हुए बताया कि 'एम्स की ये संस्कृति है कि जान निकल जाएगी, लेकिन जान बचाई जाएगी' एम्स में एक-एक मरीज पर एक-एक डॉक्टर ध्यान देता है यही एम्स की संस्कृति हैं और इसी को आगे बढ़ाना है और केवल एक स्थान पर नहीं हर जगह इस संस्कृति को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एम्स की भर्ती के लिए बनाई गई नई योजना को छात्रों के मध्य रखते हुये बताया कि एम्स में भर्तियों के समय यह ध्यान रखा जाता है कि सभी एम्स में भर्तियां एक साथ हों। ये भर्तियां इस तरह की जाती हैं कि जिस क्षेत्र का व्यक्ति हो उसे आसानी से उसी के क्षेत्र के एम्स में कार्यरत किया जा सके और क्षेत्रीय असंतुलन न हो। इसके साथ ही पूरे राष्ट्र के एम्स की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाये जो मेडिकल क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छात्रों के साथ आहवान किया कि छात्रों को ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी है और इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को विजयी बनाकर निभानी है।

नड्डा ने अंत में छात्रों से कहा कि इस नव निर्मित बिलासपुर एम्स का पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए, यह छात्रों को मिलने वाला अधिकतम अवसर है। उन्होंने कहा जिस तरह की तकलीफ हिमाचल बिलासपुर के एम्स में कार्य करने वाले लोग बताते हैं उसी तरह की समस्या दिल्ली एम्स में भी है इसलिए सभी समस्याओं को दरकिनार कर मानवता की सेवा करनी है और उसके लिए पूरी ताकत से कार्य करना चाहिए। नड्डा ने बताया कि वे आये दिन स्वास्थ्य मंत्री से देशभर में चल रहे कार्यों की प्रगति के बारे में पूछते रहते हैं और उन्हें सदैव सकारात्मक उत्तर ही मिलता है।

मोदी सरकार का तोहफा अब हिमाचल से हरिद्वार तक सीधी ट्रेन सुविधा: अनुराग ठाकुर

शिमला। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के ऊना से सहारनपुर तक चलने वाली ट्रेन की सेवा को अब हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा।

अनुराग ठाकुर ने इस बारे में फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के निवासियों को बहुत लाभ होगा और तीर्थ पर्यटन में भी वृद्धि होगी।

अनुराग ठाकुर ने कहा हिमाचल प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी सुविधाएं प्रदान करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरिद्वार प्रमुख धार्मिक स्थल है और हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग तीर्थयात्रा के लिए हरिद्वार जाते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की और ऐसे प्रावधान का अनुरोध किया ताकि हिमाचल के यात्री ट्रेन से सीधे हरिद्वार जा सकें। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है पहले ऊना से सहारनपुर तक चलने वाली ऊना हिमाचल- सहारनपुर एमईएमयू ट्रेन की सेवा के हरिद्वार तक विस्तार को रेल मंत्री ने मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन अब ऊना से हरिद्वार तक चलेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

अनुराग ठाकुर ने कहा, 'विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मोदी सरकार ने ऊना को सौगात देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। यह बीजेपी के कारण ही संभव हो पाया है कि भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन अब हिमाचल प्रदेश में चल रही है। मोदी सरकार रेलवे सेवाओं के विस्तार और हिमाचल प्रदेश में नई ट्रेनें चलाने से लेकर आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास तक कनेक्टिविटी के किसी भी मुद्दे का हल करने की दिशा में लगन से काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए 1838 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। वर्ष 2023-24 के बजट में सामरिक महत्व की भानुपाली- बिलासपुर-बेरी रेल लाइन के लिए 1000 करोड़ रुपये, चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाइन के लिए 450 करोड़ रुपये और नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 452 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। रेलवे विस्तार के लिए 1838 करोड़ रुपये की यह मंजूरी 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान मंजूर की गयी राशि की तुलना में 17 गुना अधिक है। वर्तमान में, राज्य में 19556 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 258 किलोमीटर तक फैली चार परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा वर्षों से ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न ढांचागत सुधारों की मांग की जा रही है। लोहारली खड्ड पर 500 मीटर लंबे डबल लेन पुल को मंजूरी, दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, अंब रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण और फुट ओवरब्रिज का विस्तार, ऊना रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्लेटफार्म और फुट ओवरब्रिज की मंजूरी, पुराने पुल का विस्तार, नई ट्रेनों की मंजूरी के साथ ही चुरारू टकराला अंबाला कैंट-दौलतपुर चौक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन और रायमेहतपुर सहारनपुर-ऊना हिमाचल पैसेंजर एक्सप्रेस जैसे प्रमुख ट्रेनों के स्टॉपेज को मंजूरी मिलना पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए मोदी सरकार की ओर से अहम उपहार हैं।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की अनुशंसा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक औद्योगिक पैकेज की घोषणा की थी जिसका सीधा लाभ ऊना जिले में उद्योगों की स्थापना में मिला।

ऊना जिला हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला है जो ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन से जुड़ा है। पहली ट्रेन वर्ष 1990 में ऊना पहुंची थी।

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से मार्च 2019 तक अंब-अंदौरा, चिंतपूर्णी मार्ग और दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशनों का काम पूरा हुआ। आज ऊना और अंब अंदौरा रेलवे स्टेशनों से इस जिले को देश के विभिन्न हिस्सों से कुल 13 ट्रेनें जोड़ती हैं। ऊना से साबरमती रेलवे स्टेशन तक दैनिक ट्रेन सेवाएं भी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऊना-हमीरपुर रेलवे लाइन की घोषणा 2019 में धर्मशाला में आयोजित इन्वेस्टर मीट में की थी। असल में इस रेलवे लाइन को तीन बार आर्थिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया और 2014 से 2019 तक लोकसभा रेल बजट प्रस्तुतियों में इसके निर्माण के लिए कदम उठाने पर जोर दिया गया। हालांकि, इस घोषणा ने तब गति पकड़ी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हुए इस रेलवे लाइन की अहमियत बताई और व्यक्तिगत रूप से इसका निर्माण शुरू करने के लिए रेलवे मंत्रालय को निर्माण पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश भी दिया ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

अनुराग ठाकुर ने कहा, यह रेलवे लाइन मां ज्वालामुखी, मां चिंतपूर्णी, मां ब्रजेश्वरी, मां चामुंडा आदि तीर्थ स्थानों को जोड़ते हुए राज्य में धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाएगी, जिससे राज्य के राजस्व में योगदान मिलेगा। इसके अलावा, इससे भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में सेवारत युवाओं को क्रमशः हमीरपुर और मंडी जिलों में सरकाघाट और धर्मपुर तहसीलों के साथ-साथ कांगड़ा जिले में पालमपुर, बैजनाथ, जयसिंहपुर तहसीलों से यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन का लाभ मिलेगा।

ऊना-हमीरपुर रेलवे लाइन के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार 1500 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार 4300 करोड़ रुपये का योगदान देगी।

अनुराग ठाकुर ने कहा, 17 फरवरी को नदी पर एक पुल के निर्माण की मंजूरी मिल गयी। इससे पठानकोट और जोगिंदरनगर के बीच रेल सेवा की बहाली में तेजी आएगी। इसके साथ ही कांगड़ा और नूरपुर के बीच रेल ट्रैक भी जल्द बहाल किया जाएगा। इसके लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रेल मंत्री से भी मुलाकात की है।

प्रतिभा सिंह ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में किए विभिन्न विकासात्मक कार्यों के शिलान्यास

शिमला/शैल। सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विद्युत

समस्याएं सुनी तथा संबंधित विभागों को जल्द निपटारे के निर्देश दिए।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जयदेवी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरण किए।

प्रतिभा सिंह ने पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों को बधाई दी तथा अन्य बच्चों को अधिक मेहनत करने की सलाह दी और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के समय लोगों की हर संभव मदद की है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का वर्ष 2024-2025 का बजट उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का बजट है जिसमें समाज के सभी वर्गों के विकास का ध्यान रखा गया है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना में स्वरोजगार के अवसर तथा नई स्टार्टअप नीति से युवा विकास को नई मजबूती मिलेगी।

बजट में किसान वर्ग का भी विशेष ध्यान रखा गया है। दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्राकृतिक रूप से उगाये गेहूँ को 40 रुपये तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। इन निर्णय से जिले के किसानों बागवानों को सीधा लाभ होगा। मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये की बढ़ौतरी करके दिहाड़ी 300 रुपये करने के निर्णय, वहीं मनरेगा कामगारों को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता देने के एलान, बजट में आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय 12 हजार रुपये करने, बुजुर्गो के लिए मुख्यमन्त्री सुख आरोग्य योजना चलाने तथा इसके जरिए 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी ऐसे वृद्धों, जोकि आयकर न दे रहे हों, को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10 हजार रुपये करने की घोषणा की गई है।

प्रतिभा सिंह ने महिला मंडल चांबी और कला मंच को फर्नीचर के लिए सम्भव धनराशि देने तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जयदेवी के विकासात्मक कार्यो के लिए रखी गई विभिन्न मांगों को पूरा करने की घोषणा की।

न्यूज वेब चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स/पोर्टल और सोशल मीडिया हैन्डलर्स के मनोनयन के लिए आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा न्यूज वेब चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स/पोर्टल और सोशल मीडिया हैन्डलर्स के मनोनयन (इम्पैनलमेंट) के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों व अन्य पहलों के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 हाल ही में अधिसूचित की गई है। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस नीति का उद्देश्य न्यूज वेब चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स/पोर्टल और सोशल मीडिया हैन्डलर्स के माध्यम से प्रदेश सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और विकासात्मक पहलों को जन-जन तक प्रचारित एवं प्रसारित करना है।

विभाग में मनोनयन के लिए इन चैनल्स, पोर्टल्स और हैन्डलर्स को सामान्य एवं तकनीकी योग्यता पूर्ण करनी होगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल मीडिया नीति की प्रति विभाग की वेबसाइट http://www.himachalpr.gov.in. पर उपलब्ध है और इस नीति के प्रावधानों के बारे में इससे जानकारी प्राप्त कर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन का प्रारूप भी इसी नीति दस्तावेज के साथ संलग्न किया गया है। मनोनयन के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, शिमला-2 के कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।

पोषण सुरक्षा में सब्जियों की भूमिका अहम

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के सब्जी विज्ञान विभाग में 'बागवानी में उन्नत संकाय प्रशिक्षण केंद्र' ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 17

वैज्ञानिकों के लिए 'विविध सब्जी उत्पादन के माध्यम से पोषण सुरक्षा' विषय पर 21 दिवसीय का राष्ट्रीय स्तर के उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित किया गया।

समापन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुये अनुसंधान निदेशक और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. संजीव चौहान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के गरीबी मुक्त, शून्य भुखमरी और अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने के लिए सब्जियां की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सब्जियां आहार का एक अभिन्न अंग हैं और हमारी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हैं। डॉ. चौहान ने प्रतिभागियों से कृषि विस्तार और ऐसे अनुकरणीय मॉडल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया जो किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की जरूरतों को पूरा कर सकें। विशिष्ट अतिथि और हॉर्टिकल्चर कॉलेज के पूर्व डीन डॉ. उमेश कुमार कोहली ने फसलों के विविधीकरण में सब्जियों की भूमिका और कुछ सब्जियों की किस्मों के बड़े पैमाने पर प्रसार में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

दोनों वक्ताओं ने उच्च पोषण मूल्यों के साथ विविध सब्जी उत्पादन के लिए सब्जियों की सफल प्रौद्योगिकियों और किस्मों को विकसित करने के लिए भविष्य की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करने की बात की। उन्होंने नई प्रौद्योगिकियों के त्वरित विकास और किसानों को उनके हस्तांतरण तथा देश की बढ़ती आबादी की पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उत्पादकता में वृद्धि की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

इससे पहले सब्जी विज्ञान विभाग के विभागअध्यक्ष डॉ. हैप्पी देव शर्मा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण में हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 17 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। देश के कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने विविध सब्जी उत्पादन और पोषण सुरक्षा के अत्याधुनिक अनुसंधान पहलुओं पर व्याख्यान दिये। इस प्रशिक्षण में विचार-विमर्श बढ़ती आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान अत्याधुनिक सब्जी प्रौद्योगिकी पर केंद्रित रहा। डॉ. शर्मा ने बताया कि यह केंद्र 1994 से विभाग में चल रहा है और सब्जियों के विभिन्न अनुसंधान और विकास पहलुओं पर वर्तमान प्रशिक्षण को मिलकर 33 उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 600 से अधिक वैज्ञानिकों ने अपने कौशल को उन्नत किया है। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये और प्रशिक्षण का एक सार-संग्रह भी जारी किया गया। प्रशिक्षण के सह-समन्वयक डॉ. मीनू गुप्ता के धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। डॉ. मनीष शर्मा, डीन, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, डॉ.सीएल ठाकुर, डीन कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, डॉ.केके रैना, लाइब्रेरियन और सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री की श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ऊना जिले के हरोली उपमंडल के गांव गोंदपुर जयचंद में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री की श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा में शामिल हुये। उनका

9 फरवरी को आकस्मिक निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री का आकस्मिक निधन परिवार विशेषकर मुकेश अग्निहोत्री और उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि दु:ख की इस घड़ी में उन्हें एक-दूसरे का भावनात्मक सहारा बनना होगा। प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री परिवार के लिए एक बड़ी ताकत और सहारा थीं। उनके विचारों और सरल स्वभाव का अनुसरण करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

उन्होंने कहा कि प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री एक असाधारण शिक्षाविद् होने के साथ-साथ एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। शिक्षा एवं सामाजिक कार्यो के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। महिला उत्थान और सशक्तिकरण के लिए वह प्रेरणास्रोत रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विश्वविद्यालय के दिनों से ही उनसे परिचित था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सादगी और समर्पण से सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल किया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्हें कभी प्रोफेसर सिम्मी से मिलने का अवसर नहीं मिला। इस प्रार्थना सभा में भाग लेकर उन्होंने महसूस किया कि प्रोफेसर सिम्मी एक बहुआयामी प्रतिभाशाली महिला थीं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र और सामाजिक कार्यो के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

स्व. प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री के जीवन और कार्यो पर एक वृत्तचित्र भी दिखाया गया।

कृषि मंत्री चंद्र कुमार, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक राम कुमार, संजय रतन, भवानी सिंह पठानिया, सुदर्शन बबलू और नीरज नैय्यर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, डीसीसी अध्यक्ष रणजीत सिंह राणा, उपायुक्त जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, कांग्रेस के नेता और अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बजट में भेड़-बकरी पालकों के हितों का रखा गया है विशेष ध्यान:विधानसभा अध्यक्ष

शिमला/शैल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में भेड़ पालकों के हितों का ध्यान रखते हुए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त

धनराशि का प्रावधान किया है।

कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सूक्खु द्वारा प्रस्तुत बजट में भेड़-बकरी पालकों की बड़ी समस्याओं में डिप्पिंग और ट्रेंचिंग की व्यवस्था में सुधार के प्रावधान करने के साथ भेड़ों की ऊन कटाई की मौजूदा व्यवस्था में सुधार करके परम्परागत चरानों तथा रास्तों का पुनरू निर्माण, ऊन के व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आए बदलाव के कारण ऊन के खरीद मूल्य में भारी गिरावट के बावजूद उचित व्यवस्था करना, प्रदेश में भेड़-बकरियों के लिए एफएमडी वैक्सीनेशन शुरू करने तथा विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए एक नई योजना 'भेड़-बकरी पालक प्रोत्साहन योजनाष प्रारम्भ करने की घोषणा से भेड़ पालक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

यहां खास बात यह है कि प्रदेश में जहाँ 8 लाख भेड़ें तथा 11 लाख बकरियों की संख्या हैं वहीं ज़िला में भेड़ पालकों के पास भेड़ 245560 तथा 225361 बकरियां है । वर्तमान में भी कई परिवारों की आर्थिकी का आधार भेड़-बकरी पालन व्यवसाय है ।

प्रदेश सरकार के इस निर्णय से भेड़-बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी।

केंद्र की योजनाओं के सहारे चल रहा प्रदेश:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश सिर्फ़ केंद्र की योजनाओं के सहारे आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में विकास के जो भी काम चल रहे हैं वह केंद्र द्वारा ही

चलाये जा रहे हैं। राज्य सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो गई है। हवा-हवाई बातों के अलावा सुक्खू सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार एक तरफ़ मातृशक्ति को विधायिका में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन क़ानून लेकर आयी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं को महिला केंद्रित करके देश की करोड़ों महिलाओं को लाभ दे रही है। वहीं हिमाचल की सुक्खू सरकार नारी सम्मान निधि न देने के बहाने खोज रही है। ऐसी जगहों से योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर रही है जहां पर महिलाओं की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सके। जबकि वादा 23 लाख महिलाओं को देने का था। यह बात उन्होंने बीजेपी के संगठनात्मक ज़िला महासू के रोहडू मण्डल में महिला मोर्चा के कार्यक्रम में कही।

जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार किसी भी विषय को लेकर गंभीर नहीं हैं। बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेज पार्क के मामले में सरकार द्वारा अपरिपक्वता के साथ काम किया जा रहा है। उद्योग और विकास विरोधी काम करके प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हर दिन प्रदेश में किसी न किसी प्रकार की मदद मिल रही है, नई-नई योजनाएँ आ रही हैं। एक दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स बिलासपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली मशीनें समर्पित करके गये हैं और अब एक दिन बाद प्रधानमंत्री ऊना में अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर अस्पताल की आधारशिला रखने जा रहे हैं। यह अस्पताल गंभीर अवस्था के मरीज़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार के दूसरे बजट से साफ़ है कि यह सरकार गंभीरता से काम नहीं कर रही है और न ही प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने की कोई मंशा है। बजट सरकार के संकल्पों की सिद्धि का रोडमैप होता है लेकिन सुक्खू सरकार का बजट तो पहले बजट की कॉपी भर है, जिसमें घोषित योजनाएं जमीन पर उतारे जाने के लिए सरकार की राह देख रही हैं। अब सरकार के भीतर से लेकर जनता के अंदर से एक ही आवाज आ रही है कि इस सरकार के बस का कुछ नहीं हैं। हर तरफ़ निराशा का माहौल है।

ब्रिटिश उच्चायोग और एचपीसीए के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। ब्रिटिश उच्चायोग और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की।

ब्रिटिश उच्चायोग के उप प्रमुख अमनदीप ग्रेवाल और ब्रिटिश सरकार में राजनैतिक, प्रेस और परियोजना सलाहकार राजेंद्र एस. नागरकोटी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री

को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में सात मार्च को आयोजित होने वाले यूके-एचपीसीए के संयुक्त स्वागत समारोह के लिए निमंत्रण दिया। भारत और ब्रिटेन की टीमों के मध्य खेले जाने वाले पांचवे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन समारोह के आयोजन का उद्देश्य ब्रिटेन और हिमाचल के मध्य सौहार्दपूर्ण एवं मजबूत रिश्ते को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर ब्रिटिश और हिमाचली व्यंजन भी परोसे जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि विशिष्ट अतिथियों के साथ भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलिक्स एलिस भी स्वागत समारोह में शामिल होंगी। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरित हाईड्रोजन, इलैक्ट्रिक वाहन, पर्यटन और जन निकायों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ सहयोग की भावनाएं तलाशने में गहरी रूचि दिखाई। उन्होंने ब्रिटिश दल से संयुक्त लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटेन की विशेषज्ञता का उपयोग करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के साथ मिलकर सहयोग करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सहयोग पर विचार-विमर्श के लिए ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के साथ शीघ्र ही बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि हिमाचल प्रदेश ब्रिटेन के साथ साझेदारी का अधिकतम उपयोग कर सके।

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक सुरेन्द्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री को भारत और इंग्लैड के मध्य क्रिकेट टैस्ट मैच देखने के लिए आमंत्रित किया।

राज्य सांसद सिकंदर ने भरा युवाओं में जोश

शिमला/शैल। व्हाइट हाउस गजेरि में भाजयुमो की मण्डल कार्यशाला में डॉ. सिकंदर राज्यसभा सांसद, प्रदेश महामंत्री

भाजपा एवं प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज ने भाग लिया। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को युवा चोपाल कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण दिया।

डॉ. सिकंदर ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत ने 10 वर्षों में फ्रैजाइल 5 से टॉप 5 का सफ़र तय किया है। भारत अब 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 2047 से पहले 'विकसित भारत' का सपना जरूर साकार होगा क्योंकि ये 'नरेन्द्र मोदी की गारंटी' है। हमारी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर हाल के वर्षों में लगातार दुनिया में सबसे अधिक बनी हुई है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। पीएम गति शक्ति योजना, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जैसी योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था की काफी मजबूत किया है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, मुद्रा योजना, रोजगार मेला, पर्यटन नीति, ड्रोन पॉलिसी, डिफेंस कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, इकॉनोमिक कॉरिडोर जैसे कई इनिशिएटिव ने देश में रोजगार के असीम अवसर उत्पन्न किये हैं। रोजगार मेला के तहत कुछ ही महीनों में अब तक लगभग 8 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। बैंकिंग क्षेत्र में सराहनीय पुनरुद्धार हुआ है और पूरे वित्तीय क्षेत्र की सेहत में सुधार हुआ है। सकल एनपीए सितंबर 2023 में दशक के निचले स्तर 3.2% पर है, जो 2017-18 में अपने चरम मूल्य 11.2% से काफी कम है। पिछले तीन वर्षों में भारत लगातार 7% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। 2014-24 के दौरान औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.1% है। 2014 में लगभग सभी स्मार्टफोन आयात करने के बाद, भारत में स्मार्टफोन के घरेलू उत्पादन में 11 गुना वृद्धि देखी गई और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बन गया है, जिसने पिछले साल अकेले 1,00,000 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन का निर्यात किया था।

1900 रुपए बढ़ाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस सचिव सुमन ठाकुर

की अगुवाई में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और वर्ष 2024-25 के बजट में उनके मानदेय में प्रतिमाह 1900 रुपए की बढ़ौतरी करने के लिए आभार व्यक्त किया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। यही नहीं, राज्य सरकार ने चार प्रतिशत महंगाई भत्ता की किस्त देने की घोषणा कर दी है और आने वाले समय में भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिये जाएंगे।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार में सभी कर्मचारियों के हित सुरक्षित हैं और मुख्यमंत्री ने पिछले 14 माह के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों को अनेक लाभ प्रदान किए हैं। पिछले बजट में भी राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 2000 रुपए की वृद्धि की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 1321 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं और सभी इस ऐतिहासिक बढ़ौतरी के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं।

प्रतिनिधिमंडल में सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य तथा पदाधिकारी उपस्थित थे।

सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने जेओए आईटी अभ्यर्थीयों का मुद्दा सदन में उठाने का आश्वासन दिया

शिमला/शैल। कांग्रेस की पूर्व सरकार में मंत्री और वर्तमान में विधायक सुधीर शर्मा और कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा चौड़ा मैदान में अनशन पर बैठे जेओए आईटी के अभ्यार्थियों से मिलने चौड़ा मैदान पहुंचे। जहां उन्होंने उनका हाल जाना और अभ्यार्थियों के मामले को सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। पहले भी सुधीर शर्मा और राजेन्द्र राणा सरकार से इनका परिणाम घोषित करने की मांग उठा चुके है। राजेन्द्र राणा ने तो खुला पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था। वही धरना स्थल पर जा कर दोनों ही विधायको ने इनका दर्द जाना और सदन के अन्दर इस मामले को उठाने का आश्वासन दिया। यही नही दोनो विधायकों ने अभ्यार्थियों की मदद भी की। सुधीर शर्मा ने पर्स में रखे सब पैसे डोनेशन बॉक्स में डाल दिये। राजेंद्र राणा ने भी पैसे दान बॉक्स में डाले।

कांग्रेस विधायक और पूर्व की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने JOA IT अभ्यार्थियों का मुद्दा सदन में उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी प्रदेश में विकराल समस्या है उन्होंने कहा कि यह समस्या अभी भी बनी हुई है। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों ने कांग्रेस को सत्ता में लाया। उन्होंने कहा कि इन अभ्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए। सुधीर शर्मा ने कहा कि वह पहले भी अभ्यर्थियों का मामला उठाते आये हैं। इस दौरान उन्होंने राजेंद्र राणा के पत्र का भी जिक्र किया। सुधीर शर्मा ने कहा कि वे इस मामले को सदन उठाएंगे जिसके बाद वास्तव स्थिति का पता चलेगा।

वही इस मौके पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि अभ्यार्थियों ने अपनी स्थिति के बारे में उन्हें बताया है और उच्चतम न्यायालय की जजमेंट कॉपी दी है उन्होंने कहा की लोकतंत्र में अपनी बात उठाने का हक हर किसी को है और अभ्यार्थी भी आन्दोलन कर सकते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि वे चुने हुये प्रतिनिधि होने के नाते अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी अभ्यार्थियों की आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले को सदन में उठाएंगे और इन अभ्यार्थियों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कांग्रेस को सीटें जीतने के लिये मंत्रियों या उनके परिजनों को चुनाव में लड़वाना होगा

- मंत्रियों के चुनाव लड़ने से उनको सरकार की लोकप्रियता का पता चल जायेगा
- गारंटीयों पर सरकार के दावों की परीक्षा होंगे यह चुनाव
- व्यवस्था परिवर्तन पर जनता की प्रतिक्रिया की व्यवहारिक जानकारी होंगे यह चुनाव

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस चुनावी सर्वेक्षण के आधार पर लोकसभा उम्मीदवारों का चयन करेगी यह कहना है प्रदेश के लिये नियुक्त स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री भगत चरण दास का। सभी दल प्राय: इसी सिद्धान्त पर उम्मीदवारों का चयन करते हैं। स्मरणीय है कि सर्वे इस संबंध में पहले भी हो चुका है और उसके अनुसार सीटों पर पार्टी की हालत कमजोर पायी गई है। अभी राज्यसभा की भी एक सीट के लिये एक सर्वेक्षण चर्चा में आया है जिसके मुताबिक भाजपा की जीत 67 प्रतिशत और कांग्रेस की 33 प्रतिशत आंकी की गई है जबकि कांग्रेस की सरकार है। जब कोई पार्टी सरकार में होती है और तब चुनावी सर्वेक्षण होता है तो उसमें सरकार की परफारमैन्स सरकार और संगठन में तालमेल और जनता में बन रही छवि मुख्य आधार रहते हैं। राज्य में सरकार होने की स्थिति में पार्टी की राष्ट्रीय नीतियां बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहती है क्योंकि आम आदमी वक्त की सरकार से ज्यादा प्रभावित रहता है। जब केन्द्र और राज्य में अलग – अलग दलों की सरकार होती है तब यह भी देखा जाता है कि प्रदेश की सरकार में से केन्द्र की सरकार की नीतियों पर कितनी आक्रामकता अपनायी गयी है।

सर्वेक्षण के इन मानकों पर यदि प्रदेश की सरकार का आकलन किया जाये तो सबसे पहले और बड़ा बिन्दु यह आता है कि सुक्खू सरकार के एक भी आचरण से आज तक यह लक्षित नहीं हुआ है कि प्रदेश में कोई अलग सरकार है। शासन तक में ट्रांसफर तक हुये जब चुनाव आयोग ने एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके अधिकारियों को बदलने के आदेश दिये। एक तरह से पक्ष और विपक्ष रस्म अदायगीयों की औपचारिकताओं से आगे नहीं बढ़े हैं। जब सरकार अपनी ही पार्टी द्वारा चुनावों में सार्वजनिक रूप से जारी किये गये आरोप पत्र पर कोई कारवायी न कर पाये तो उसका चुनावी आकलन क्या किया जायेगा। कांग्रेस ने चुनावों के दौरान दस गारंटीयां जारी की थी उनकी पूर्ति के लिये सरकार ने क्या व्यवहारिक कदम उठाये हैं और क्या उपलब्धियां इसका राज्यपाल के अभिभाषण तक में कोई ठोस जिक्र नहीं है। अभी उपलब्धियों का जो विज्ञापन जारी किया जा गया है उसमें भी गारंटीयों का कोई उल्लेख नहीं है। इन गारंटीयों को लेकर कांग्रेस के अपने ही विधायक विधानसभा के अन्दर न केवल सवाल ही पूछ रहे हैं बल्कि खुला पत्र लिखने की नौबत तक पहुंच गये हैं।

शिखर सम्मेलन में विदेशी मेहमानों के लिये राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में केवल हिमाचल के ही मुख्यमंत्री शामिल हुये थे बाकी कांग्रेसी मुख्यमंत्री इससे बाहर रहे थे। अब राम मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी हिमाचल सरकार ने ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया और इसके तीन नेता इसमें शामिल हुये। आने वाला लोकसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस में गंभीर आरोपों – प्रत्यारोपों का अखाड़ा होगा। इसमें हिमाचल कांग्रेस के नेता किस मुंह से मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल पायेंगे। सरकार और संगठन में तालमेल की क्या स्थिति है इसको लेकर समय – समय पर प्रदेश अध्यक्षा के ब्यान ही अपने में बड़े प्रमाण हैं। कर्मचारियों के कितने वर्ग धरने प्रदर्शनों के लिये मजबूर हो चुके हैं यह सबके सामने है। इस वस्तु स्थिति में होने वाले चुनावी सर्वे के परिणाम क्या होंगे इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। आज स्थिति पार्टी में पदाधिकारी के त्यागपत्रों तक पहुंच गई है। हाईकमान के आचरण से भी यही झलक रहा है कि उसके लिये मुख्यमंत्री के दावे ही अन्तिम सच हैं या उसने हिमाचल को उसके हाल पर ही छोड़ दिया है। जबकि भाजपा इस चुनाव में साम – दाम – दण्ड और भेद के सारे सूत्र एक प्रयोग करके चल रही है। आने वाले दिनों में यदि कुछ मंत्रियों के खिलाफ भी सनसनी खेज दस्तावेजी खुलासे सामने आ जायें तो कोई हैरानी नही होगी।

इस समय यदि हाईकमान प्रदेश और लोकसभा चुनाव के लिये गंभीर है तो उसे चारों सीटों से किसी न किसी मंत्री को ही चुनाव में उतरना चाहिये। इससे पार्टी के प्रति इन लोगों की निष्ठाओं से ज्यादा इनकी परफारमैन्स का भी टेस्ट हो जायेगा। क्योंकि सरकार के दावों का फील्ड में व्यवहारिक सच क्या है और व्यवस्था परिवर्तन के जुमले पर आम आदमी की प्रतिक्रिया क्या है इसका इनको प्रत्यक्ष ज्ञान हो जायेगा। इस समय हमीरपुर लोकसभा सीट पर लम्बे अरसे से कांग्रेस हारती चली आ रही है। आज मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों इसी हमीरपुर क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। इसलिये इस सीट से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी से ज्यादा प्रभावी उम्मीदवार कौन हो सकता है। फिर सरकार और मुख्यमंत्री के दावों की व्यवहारिक परीक्षा भी हो जायेगी। यही नहीं कमलेश ठाकुर के प्रत्याशी बनने से प्रदेश के चुनाव में गंभीरता भी आ जायेगी। चारों सीटों पर इसी तरह का प्रयोग किया जाना चाहिये अन्यथा प्रदेश से कोई भी सीट कांग्रेस को मिल पाना संभव नहीं होगा।

जब सचेतक नियुक्त

पृष्ठ 1 का शेष

उल्लंघना पर कोई कारवाई नही होती।

ऐसे में यह स्थिति बनी हुई है कि जब सचेतक नियुक्त ही नहीं है तो सचेतकीय परिपत्र कौन जारी करेगा? यदि पार्टी के नाराज विधायक बजट के भी विरोध में वोट कर देते हैं तब भी उनके खिलाफ कारवाई नही होगी। इस समय पार्टी जो ऐजैन्ट नियुक्त कर रही है वहां सचेतक की भूमिका नहीं निभा सकते। ऐजैन्ट केवल सदस्यता का सत्यापन कर सकता है वह वोट के लिये निर्देश जारी नहीं कर सकता। पार्टी जब मन्त्रियों को सचेतक बनाने का प्रयास करेगी तो अपरोक्ष में उसका अर्थ हो जाता है कि उसे मन्त्रियों पर भी भरोसा नहीं रहा है। मुख्यमंत्री ने एक समय स्वयं सचेतकों की नियुक्तियों को शायद लटकाया था और आज वही गले की फांस बन गया है। इसलिये यदि चुनावों में क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो किसी के भी खिलाफ कारवाई नहीं हो सकती क्योंकि इससे सरकार नही गिरती।

क्या सुक्खू सरकार

पृष्ठ 1 का शेष

सरकार की जो स्थिति चल रही है उसमें प्रदेश की वरिष्ठ नौकरशाही ने कान्ट्रेक्ट का विकल्प तलाशने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छ: फरवरी को एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में अठारह वरिष्ठ नौकरशाहों ने भाग लिया। इस बैठक में अदालती आदेशों की अनुपालना करने से बढ़ने वाले आर्थिक बोझ से बचने के लिए गुजरात मॉडल अपनाने पर चर्चा की गई। इसमें प्रधान सचिव कार्मिक को गुजरात मॉडल का अध्ययन करने और उसकी कानूनी स्थिति जांचने की जिम्मेदारी दी गई है। अफसरशाही के इस प्रयास का सीधा सा अर्थ है कि सरकार नौकरी देने के लिये ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिसमें वित्तीय बोझ कम से कम पड़े। दूसरे शब्दों में अब सरकार ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिसमें सरकार पर कोई बाध्यता न पड़े। कहने के लिये तो सरकारी नौकरी हो परन्तु व्यवहार में नहीं। सरकार के इस प्रयास का बेरोजगार युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका पता आने वाले समय में चल जाएगा।

यह तय हुआ है अफसरशाही की बैठक में

PROCEEDINGS OF THE MEETING HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE CHIEF SECRETRY TO THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH ON 06.02.2024 TO DISCUSS THE ISSUES REGARDING CONTRACT APPOINTMENT IN THE SERVICES AND DIRECTIONS OF HON'BLE COURTS FOR COUNTING OF CONTRACT SERVICE FOR THE BENEFIT OF SENIORITY AND PROMOTION ETC.

The following were present:-

1. Shri Onkar Chand Sharma, IAS
   Additional Chief Secretary (Revenue, TD & JSV) to the Government of Himachal Pradesh.
2. Shri R.D. Nazeem, IAS
   Principal Secretary (Tpt., Ind. & FCS&CA) to the Government of Himachal Pradesh.
3. Shri Devesh Kumar, IAS
   Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh.
4. Shri Amandeep Garg, IAS
   Principal Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh.
5. Shri Priyatu Mandal, IAS
   Secretary (RD & PR) to the Government of Himachal Pradesh.
6. Shri Rakesh Kanwar, IAS
   Secretary (Education, AH & LAC) to the Government of Himachal Pradesh.
7. Shri Sharad Kumar Lagwal,
   LR-cum-Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.
8. Shri Neeraj Kumar, IAS
   Special Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh.
9. Shri Satpal Dhiman, HFS
   Additional Secretary (ES&T) to the Government of Himachal Pradesh.
10. Shri Ajay Gupta
    Engineer-in-Chief,
    Public Works Department.
11. Shri Rajinder Sharma,
    Joint Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh.
12. Shri Sharwan Kumar Negi,
    Joint Controller (Finance-Pension)
13. Shri Y.R. Sharma
    Deputy Secretary, HP Public Service Commission
14. Shri Balbir Singh
    Deputy Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh.

Page 1 of 5

alternative modes of future recruitments. It was discussed that under the State Government, a policy should be framed for future recruitments on the basis of policy framed by the Government of Gujarat for which, the services of a consultant may be engaged to finalize the policy. It was decided that the Principal Secretary (Personnel) may also take the latest update from the Gujarat Government regarding the legal status of their policy framed for recruitment.

5. The following decisions were also taken in the meeting after detailed deliberations:-

- In the case of Sheela Devi, the Department of Ayush will put-up the file to the Chief Secretary incorporating all the advices they have received from the Advisory Departments, Ld. Advocate General and Ld. Senior Advocate of the Supreme Court of India so far in the matter. They will also frame specific questions regarding the implications of the orders of Hon'ble Apex Court by the A.D.
- In the case of Taj Mohammad and others Versus State of Himachal Pradesh & Ors, the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department will take the advice of Department of Personnel and then refer the matter to the Law Department. It is to be seen whether this case can be distinguished on accounts of peculiar facts of the case.
- Since the foundation of the order dated 03.08.2023 passed by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in the cases of Taj Mohammad and others (CWP No.2004/2017) & State of HP and others versus Lekh Ram and others (CWP No.629/2018) is the judgment passed in Narender Singh Naik's case, therefore:-
  - the latest status of Narender Singh Naik's case whether the same has been implemented or not needs to be ascertained.
  - simultaneously, it has to be examined whether the case of Taj Mohammad and others (CWP No.2004/2017) & State of HP and others versus Lekh Ram and others (CWP No.629/2018) are similarly situated to that of Narender Singh Naik's case or not?

Page 4 of 5